



सत्यमेव जयते

::आयुक्त (अपील-II) का कार्यालय,केंद्रीय उत्पाद

शुल्क::

O/O THE COMMISSIONER (APPEALS-II), CENTRAL EXCISE,
7th Floor, Central Excise
Building,
Near Polytechnic,
Ambavadi,
Ahmedabad:380015



रजिस्टर डाक ए.डी.द्वारा

क फाइल संख्या (File No.): V2(85) 14/EA-2/Ahd-II /Appeals-II/ 2015-16 / 1239 to 1243
स्थगन आवेदन संख्या(Stay App. No.):

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): AHM-EXCUS-002-APP- 100 -16-17
दिनांक (Date): 27.03.2017, जारी करने की तारीख (Date of issue): 31/03/17

श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील-II) द्वारा पारित
Passed by Shri Uma Shanker, Commissioner (Appeals-II)

ग _____ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-I), अहमदाबाद- II, आयुक्तालय द्वारा जारी
मूल आदेश सं _____ दिनांक _____ से सृजित
Arising out of Order-In-Original No. 06/AC/DEMAND/15-16 Dated: 14/09/2015
issued by: Assistant Commissioner., Central Excise (Div-I), Ahmedabad-II

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s Systronics (India) Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:

(1) (क) (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

U. File



- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनोंक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

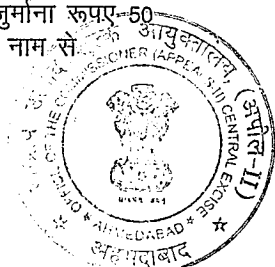
- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मेटल हॉस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद-380016.

- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से



रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग" (Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

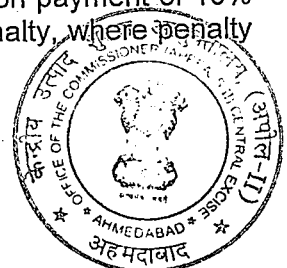
For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो मांग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

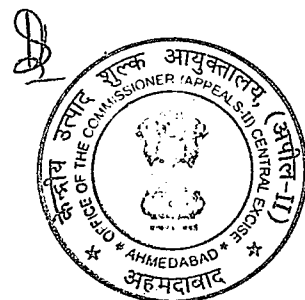
The Assistant Commissioner, Central Excise, Division-I, Ahmedabad-II, Ahmedabad (hereinafter referred to as '*the appellant*'), has filed the present appeal against the Order-In-Original No. 03/AC/DEMAND/2015-16 dated 14.09.2015 (hereinafter referred to as '*the impugned order*') passed in the matter of M/s Systronics (India) Ltd, Div. Systronics (herein after referred to as '*the respondents*') by the Assistant Commissioner, Central Excise, Division-I, Ahmedabad-II, Ahmedabad (hereinafter referred to as '*the adjudicating authority*').

2. The fact of the case, in brief is, respondent is engaged in the manufacturer of Electronic & Scientific Instrument & Equipments falling under chapter 85 & 90 of the first schedule to the Central Excise Tariff Act, 1944. They are availing benefit of Cenvat Credit as per Cenvat Credit Rules, 2004. During the course of Audit, for the period from October 2010 to September 2013, the Audit Party observed following observation-:

- (1) Wrong availment of Education Cess & Higher Education Cess.
- (2) Short Payment of Duty as per Rule 16 of Central Excise rules, 2002 in respect of Return Finished Goods from Exhibition.
- (3) Wrong availment of Service Tax Credit on software maintenance services which is commonly used by all other branches as well as head office of the assessee.
- (4) Wrong availment of Service Tax Credit on manpower supplier service which is commonly used by the assessee manufacturing unit as well as head office.

The amount involved in the above observation is ₹ 3,70,405/- and interest involved ₹ 85,143/-. Accordingly Respondent was issued Show Cause Notice proposing as to why Cenvat Credit of ₹ 3,70,185/- wrongly availed by them should not be recovered. Why interest should not be recover. Why Penalty should not be imposed. The Adjudicating Authority vide impugned order confirmed the demand of ₹ 3,70,185/- . Penalty of ₹ 1,85,203/- was also imposed under Rule 15(2) of Cenvat Credit Rules, 2004, read with Section 11AC (1) (b) of The Central Excise Act, 1944. Demand of interest was also confirmed.

3. The said impugned order was reviewed by the Commissioner of Central Excise, Ahmedabad-II on the ground that the adjudicating authority has erred by applying the penal provision under the provision of Rule 15(2) of Cenvat Credit Rules, 2004, read with Section 11AC (1) (b) of The Central Excise Act, 1944, which relate to cases where suppression, misstatement etc (elements of deception) are not attracted. Since suppression was upheld by the adjudicating authority, therefore he has to invoke penal provision of under Section 11AC 1(c) .



4. Personal hearing in the matter was granted to the respondent on 09.12.2016, however they requested for extension of time limit. Second personal hearing was granted on 20.12.2016 which was attended by their authorized representative. The respondent has filed the reply against appeal filed by the appellant. They further submitted their written submission on 20.01.2017 requested to set aside the appeal filed by the revenue.

5. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of the appeal, and written submission put forth by the respondent. Looking to the facts of the case, I proceed to decide the case on merits.

6. In the present case, I find that the Adjudicating Authority vide impugned order confirmed the demand of ₹ 3,70,185/- and Penalty of ₹ 1,85,203/- was also imposed under Rule 15(2) of Cenvat Credit Rules, 2004, read with Section 11AC (1) (b) of The Central Excise Act, 1944. Demand of interest was also confirmed. The Appellant is in a view that respondent was less penalised under the provision of Rule 15(2) of Cenvat Credit Rules, 2004, read with Section 11AC (1) (b) of The Central Excise Act, 1944, which relate to cases where suppression, misstatement etc (elements of deception) are not attracted. Since suppression was upheld by the adjudicating authority, therefore he has to invoke penal provision of under Section 11AC 1(c). The respondent submitted that all the observation are of the period of 30.11.2011 and afterwards. Therefore penal provision of under Section 11AC 1(c) will not apply in this case.

Therefore I have to decide the issues:-

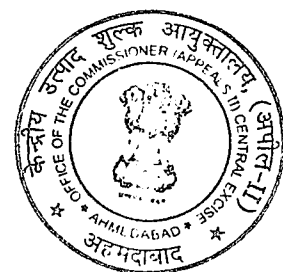
Whether adjudicating authority has rightly penalized the respondent under the penal provision of under Section 11AC 1(b) or not.

To decide the issue I hereby re-produce the relevant para of Section 11AC of The Central Excise Act, 1944 which says that -:

Section 11AC. Penalty for short-levy or non-levy of duty in certain cases -

(1) The amount of penalty for non-levy or short-levy or non-payment or short-payment or erroneous refund shall be as follows:-

(a) where any duty of excise has not been levied or paid or has been short-levied or short paid or erroneously refunded, for any reason other than the reason of fraud or collusion or any wilful misstatement or suppression of facts or contravention of any of the provisions of this Act or of the rules made thereunder with intent to evade payment of duty, the person who is liable to pay duty as determined under sub-section (10) of section 11A shall also be liable to pay a penalty not exceeding ten per cent. of the duty so determined or rupees five thousand, whichever is higher: Provided that where such duty and interest payable under section 11AA is paid either before the issue of show cause notice or within thirty days of issue of show cause notice, no penalty shall be payable by the person liable to pay duty or the person who has paid the duty and all



proceedings in respect of said duty and interest shall be deemed to be concluded;

(b) where any duty as determined under sub-section (10) of section 11A and the interest payable thereon under section 11AA in respect of transactions referred to in clause (a) is paid within thirty days of the date of communication of the order of the Central Excise Officer who has determined such duty, the amount of penalty liable to be paid by such person shall be twenty-five per cent. of the penalty imposed, subject to the condition that such reduced penalty is also paid within the period so specified;

(c) where any duty of excise has not been levied or paid or has been short-levied or short paid or erroneously refunded, by reason of fraud or collusion or any willful mis-statement or suppression of facts, or contravention of any of the provisions of this Act or of the rules made thereunder with intent to evade payment of duty, the person who is liable to pay duty as determined under sub-section (10) of section 11A shall also be liable to pay a penalty equal to the duty so determined: Provided that in respect of the cases where the details relating to such transactions are recorded in the specified record for the period beginning with 8th April, 2011 up to the date on which the Finance Bill, 2015 receives the assent of the President (both days inclusive), the penalty shall be fifty per cent. of the duty so determined;

It is clear from above that in the present case the adjudicating authority in his order held that the respondent has willfully mis-statement or suppression of facts by way of not intimating the department about Cenvat credit availed by them. Therefore Appellant contention is right that in the present case penalty is to be imposed under under Section 11AC 1(c) of The Central Excise Act, 1944. However Appellant contention regarding penalty equivelent to duty is wrong as all the invoices in question are pertain to period after April, 2011. The adjudicating authority have imposed the Penalty of ₹ 1,85,203/- which is 50% of Duty demanded of ₹ 3,70,185/- and the same is as per the provision of Section 11AC 1(c). In view of the above, I modify the penalty imposed under Rule 15(2) of the Cenvat Credit Rules 2004 read with Section 11AC(C)

7. Thus, in view of discussion in paragraph 6 above and in the fitness of things, it would be just and proper the OIO is modified to the above extent.

[Handwritten signature]



8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
8. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

उमा शंकर

(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स - II)

CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

ATTESTED

S S Chowhan
(S S Chowhan) 30/3/2017
SUPERINTENDENT (APPEAL-II),
CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

To,
M/s Systronics (India) Ltd, Div. Systronics,
89-92, Naroda Industrial Estate,
Naroda GIDC, Naroda,
Dist-Ahmedabad.

Copy To:-

1. The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-II, Ahmedabad.
3. The Dy./Assistant Commissioner, Central Excise, Division-I, Ahmedabad-II.
4. The Assistant Commissioner (Systems), Central Excise, Ahmedabad-II.
5. Guard File.
6. P.A. File.

